

मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था वर्ष 2047 तक 2.1 ट्रलियिन अमेरिकी डॉलर

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय उद्योग परसिंघ (CII) की एक रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था वर्ष 2047-48 तक 2.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की क्षमता रखती है, जो वर्तमान में 164.7 बलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास है।

मुख्य बदुि

- रिपोर्ट के बारे में:
 - ॰ "**मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की परकिल्पना@2047"** शीर्षक वाली रिपोर्ट में <mark>आर्थिक विकास के ल</mark>िये एक दृष्टिकोण की रूपरेखा दी गई है, जिसमें प्रमुख क्षेत्रों, नीतिगत हस्तक्षेपों और निवश के अवसरों की पह<mark>चान</mark> की गई <mark>है, जो राज्य के प</mark>रविर्तन को गति देंगे।
 - CII के महानिदशक ने कहा कि निविश को बढ़ावा देने और विकास को गति देने के लिये समर्पित एक सक्रिय राज्य सरकार के साथमध्य प्रदेश 2047-48 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में अपना योगदान मौजूदा 4.6% से बढ़ाकर 6.0% करने की स्थिति में है।
 - ॰ इसके अलावा, रिपोर्ट इस बात पर ज़ोर देती है कि मध्य प्रदेश को अपने महत्त्वाकांक्षीविकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये, विनिर्माण और औद्योगिक विस्तार को केंद्र में रखना होगा।
- कृषिऔर विनिर्माण का योगदान: कृषि क्षेत्र वर्तमान में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 43% योगदान देता है, जबकि दीर्घकालिक विकास को बनाए रखने के लिये विनिर्माण का हिससा 2047 तक 7.2% से बढ़कर 22.2% होना चाहिये।
- रिपोर्ट का आधार: यह रिपोर्ट व्यापक डेटा विश्लेषण और हितधारक परामर्श पर आधारित है, जिसमें उद्योग जगत के नेताओं, नीति निर्माताओं और अकादमिक विशेषजञों के इनपट शामिल हैं।
 - यह मध्य प्रदेश की पूरी आर्थिक क्षमता को अनलॉक करने, सतत विकास, रोजगार सृजन और बढ़ी हुई प्रतिस्पर्द्धा सुनिश्चिति
 करने के लिये एक रूपरेखा के रूप में कार्य करती है।
- रिपोर्ट में चार प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की है:
 - ॰ परविहन बुनियादी ढाँचे का वसि्तार, जैसे मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क और एयर कार्गो हब का विकास।
 - ॰ **कुशल कार्यबल** की उपलबधता बढ़ाने के लिये कौशल विकास और कौशल पारक की सथापना।
 - व्यवसाय करने में आसानी के लिये सिगल विडो सिस्टम (SWS) की दक्षता को बढ़ाना।
 - MSME का विस्तार करने के लिये योजनाएँ, जैसे रियायती ऋण व्यवस्था, बाजार पहुँच में सुधार और तकनीकी उन्नयन।

भारतीय उद्योग परसिंघ

- CII एक गैर-सरकारी, गैर-लाभकारी, उदयोग-नेतृत्व वाला और उदयोग-प्रबंधित संगठन है।
- यह सलाहकारी और परामर्शी प्रक्रियोओं के माध्यम से उद्योग, सरकार और नागरिक समाज के साथ साझेदारी करके भारत के विकास के लिये अनुकूल वातावरण बनाने और बनाए रखने के लिये काम करता है।
- इसकी स्थापना 1895 में हुई तथा इसका मुख्यालय नई दलिली में है।